unesco

परिवर्तन का प्रारंभ

भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2023

जलवायु परिवर्तन - शिक्षा ही समाधान

सारांश

यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा यूनेस्को की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि यह एक बुनियादी मानव अधिकार और शांति स्थापित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का आधार है।

यूनेस्को शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और शिक्षा में वैश्विक और क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान करती है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करती है और लैंगिक समानता और अफ्रीका पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा के माध्यम से समकालीन वैश्विक चुनौतियों का जवाब देती है।

वैश्विक शिक्षा 2030 एजेंडा

शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में, यूनेस्को को नेतृत्व और शिक्षा 2030 एजेंडा का समन्वय करने का काम सौंपा गया है - 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा। शिक्षा, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, का अपना समर्पित लक्ष्य 4 है, जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन के लिए शिक्षा 2030 रूपरेखा, इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए एक दिशानिर्देश प्रदान करती है।

परिवर्तन का प्रारंभ
जलवायु परिवर्तन - शिक्षा ही समाधान
भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2023
सारांश

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2023 में प्रकाशित, 7, प्लेस डे फॉन्टेनॉय, 75352 पेरिस 07 एसपी, फ्रांस

और

यूनेस्को नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के लिए
1 सैन मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली 110 021, भारत
फोन: +91-11-2611 1873/5 एवं 2611 1867/9
ईमेल: newdelhi@unesco.org
वेबसाइट: https://www.unesco.org/en/fieldoffice/newdelhi

© यूनेस्को 2023

लेखक
- कार्तिकेय वी. साराभाई
  निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केंद्र
- डॉ. श्वेता आर. पुरोहित
  कार्यक्रम निदेशक (जलवायु परिवर्तन) पर्यावरण शिक्षा केंद्र

तकनीकी सहायता एवं समन्वय
- जॉयस पोअन
  कार्यक्रम विशेषज्ञ और शिक्षा प्रमुख
- अभिनव कुमार
  कार्यक्रम समन्वयक, यूनेस्को नई दिल्ली

यह प्रकाशन एट्रिब्यूशन-शेयरअलाइक 3.0 आईजीओ (सीसी-बाय-एसए 3.0 आईजीओ) लाइसेंस (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) के तहत ओपन एक्सेस में उपलब्ध है। इस प्रकाशन की सामग्री का उपयोग करके, उपयोगकर्ता यूनेस्को ओपन एक्सेस संग्रह (https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa) के उपयोग की शर्तों से बंधे होना स्वीकार करते हैं।

मूल शीर्षक: Seeds of Change: State of the Education Report for India 2023; Education to Address Climate Change; Summary.

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 2023 में प्रकाशित

इस प्रकाशन में उल्लिखित पदनाम और सामग्री की प्रस्तुति किसी भी देश, इलाके, शहर या क्षेत्र या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति, या उसकी सीमाओं के परिसीमन या सीमाओं के संबंध में यूनेस्को की ओर से कोई भी राय अभिव्यक्त नहीं करती है।

इस प्रकाशन में व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से लेखकों के हैं; जरूरी नहीं कि वे यूनेस्को के हों और संगठन के प्रति प्रतिबद्ध हो।

सामने के कवर का फ़ोटो
प्री-स्कूल के बच्चों को प्रकृति की सैर पर ले जाते हुए उन्हें पर्यावरण से प्यार करना और उसका सम्मान करना सिखाया जाता है। द प्लैनेट डिस्कवरी सेंटर, सीईई, गुजरात

ग्राफिक डिजाइन, आवरण डिजाइन और संपादन
फायरफ्लाई कम्युनिकेशन्स, नई दिल्ली
ईमेल: ayesha@firefly communications.in

फोटो
©यूनेस्को / नुनाब डिजाइन्स
इस प्रकाशन में फोटो छापने से पहले सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुमति ली गई थी।

मोंटसेराट में टाइपसेट

मुद्रण
लक्सर प्रिंट्स
भारत में मुद्रित

रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड की जा सकती है:
https://en.unesco.org/fieldoffice/newdelhi

रिपोर्ट की प्रतियों के लिए कृपया संपर्क करें:
ईशा विग: i.vig@unesco.org
रेखा बेरी: r.beri@unesco.org

परिवर्तन का प्रारंभ

भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2023

जलवायु परिवर्तन - शिक्षा ही समाधान

सारांश

unesco

कार्यकारी सारांश

शिक्षा के जरिये जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, शैक्षिक दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव महत्वपूर्ण है। हाल तक, शिक्षा में पारंपरिक विषयों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब यह बात तेजी से महसूस और स्वीकार की जा रही है कि स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी के बुनियादी पहलुओं को तत्काल शामिल किया जाए।

भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता के एकीकरण पर जोर देती है और, 2023 की राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफएसई) के माध्यम से, यह देश पर्यावरण शिक्षा को एक बहु-विषयक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है जिसका संबंध सभी विषयों से है। सभी चरणों में शिक्षा में जलवायु परिवर्तन के प्रासंगिक तत्वों को शामिल करना शिक्षार्थियों और युवाओं को जलवायु समाधान के लिए जिम्मेदार एजेंट बनने के लिए ज्ञान, कौशल, व्यवहार और पहल में समर्थ बनाता है।

यह पहचान करना भी महत्वपूर्ण है कि नीतियां, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से सोची गई हों, उन्हें ठोस कार्यों और प्रभावी कार्यान्वयन में बदला जाना चाहिए। यद्यपि एनईपी 2020 और एनसीएफ ने भारत में पर्यावरण शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव रखी है, उनकी सफलता अंततः देश भर के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में योगदान के लिए उठाए गए व्यावहारिक कदमों और बनाई गई साझेदारियों पर निर्भर करती है।

इस रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में दो एसडीजी - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4) और जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13) - के परस्पर संबंध पर केंद्रित है, विशेष रूप से लक्ष्य 4.7 (सतत विकास के लिए शिक्षा [ईएसडी] और वैश्विक नागरिकता शिक्षा) और लक्ष्य 13.3 (जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ज्ञान और क्षमता का निर्माण)।

यह रिपोर्ट भारतीय शिक्षा क्षेत्र में हितधारकों के लिए नीतियों और पहलों को सूचित करने, प्रणालीगत एकीकरण को आकार देने, कक्षा में बातचीत का मार्गदर्शन करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा में सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक संदर्भ दस्तावेज के रूप में विकसित की गई है। इसके साथ ही, यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में नीति और निर्णय निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता देने और अनिवार्य ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल और मानसिकता के साथ जलवायु कार्यों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में दो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4) और जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13) के परस्पर संबंध पर केंद्रित है, विशेष रूप से लक्ष्य 4.7 (सतत विकास के लिए शिक्षा [ईएसडी] और वैश्विक नागरिकता शिक्षा) और लक्ष्य 13.3 (जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ज्ञान और क्षमता का निर्माण)। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह उजागर करना है कि सतत विकास के ये दो तत्व एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं और नीतियों, पहलों और कार्यवाहियों को डिजाइन करके शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान करते हैं। साक्ष्य-आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए, यह रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रारंभिक स्कूल चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक समग्र जलवायु शिक्षा को व्यवस्थित रूप से शामिल करके किस तरह जलवायु कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है और जलवायु समाधान उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह, यह भी दर्शाता है कि स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर जलवायु संबंधी गतिविधियां शिक्षा प्रणाली और समाज की कमियों को कैसे कम कर सकती हैं। इन्हें देखते हुए, यह रिपोर्ट शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने की मौजूदा चुनौतियों का पता लगाती है और शिक्षा के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करने की संभावनाओं के बारे में बताती है।

अंत में, यह रिपोर्ट ठोस कार्रवाई करने की सिफारिश करती है जिन्हें भारत में सभी शिक्षा हितधारकों को देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षा को लागू करने के लिए उठाने चाहिए।

ऊपर: युवा छात्र पौधों के गमलों के रूप में प्लास्टिक की बोतलों का पुन: उपयोग करते हैं। एएसएन स्कूल, नई दिल्ली।

प्रमुख निष्कर्ष

भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा

यह रिपोर्ट इस संदर्भ में चर्चा करके शुरू होती है कि भारत शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कैसे संबोधित करता है। एक ओर शिक्षा क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों और दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण भी रेखांकित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के समग्र शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर कई ठोस और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, विशेष रूप से भारत में, बढ़ती गर्मी के तनाव और हीटवेव, अनियमित मौसम की घटनाओं, जलवायु-प्रेरित विस्थापन और प्रवासन के कारण, जो शिक्षार्थियों, उनके सीखने के माहौल और सीखने के अवसरों और परिणाम को प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न कारकों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने की मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं, विशेषरूप से देशभर में कम आय और कमजोर आबादी के लिए। इससे निपटने और कम करने का एक तरीका हरित शिक्षा है - शिक्षा के बुनियादी ढांचे और संस्थानों को जलवायु के लिए तैयार और जलवायु-लचीला बनाना (स्कूलों को हरित करना), पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन शिक्षा को एकीकृत करना (हरित पाठ्यक्रम), शिक्षकों, नीति-निर्माताओं, स्कूल को प्रशिक्षण देना, जलवायु परिवर्तन पर नेताओं और शिक्षा हितधारकों (शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणालियों की क्षमताओं को हरित करना), और जलवायु परिवर्तन को आजीवन सीखने (समुदायों को हरित बनाना) में एकीकृत करना। ये ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप (जीईपी) के चार स्तंभ हैं, जो जलवायु कार्यवाही की दिशा में एक वैश्विक पहल है, जिसे सितंबर 2022 में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा लॉन्च किया गया था, और जिसके लिए यूनेस्को सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह रिपोर्ट जीईपी के चार स्तंभों के माध्यम से भारत के शैक्षिक संदर्भ का विश्लेषण करती है, और जलवायु परिवर्तन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में मौजूद विभिन्न पहलों और नवाचारों पर प्रकाश डालती है।

भारत में, जलवायु परिवर्तन शिक्षा के महत्व को पहचाना गया है और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझ बढ़ाने के लिए कई व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें पाठ्यक्रम में जलवायु शिक्षा का नीति-स्तरीय एकीकरण शामिल है; स्कूलों और कॉलेजों के भीतर कार्यक्रम और पहल; शिक्षकों के प्रशिक्षण और संसाधनों का विकास और वितरण; युवाओं के लिए

जागरूकता अभियान और हरित-कौशल कार्यक्रम; और जलवायु-लचीले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहल। इस तरह की पहल राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, युवाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा संचालित की जाती है। यह रिपोर्ट इनमें से कुछ पहलों को पेश करती है और कई केस अध्ययनों पर प्रकाश डालती है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और अपनाने में भारतीय हितधारकों की सरलता को प्रदर्शित करते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत समाज के सभी सदस्यों को जलवायु समाधान में शामिल होने के लिए सशक्त बनाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम करता है, जैसाकि कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कहा गया है, अब इसे एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट (एसीई) के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, इस रिपोर्ट में एसीई के छह तत्वों: शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना, जागरूकता, सार्वजनिक भागीदारी और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आसपास भारत में विभिन्न नीतिगत पहल और सरकार के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों को संकलित किया गया है।

पूरे देश में, जलवायु परिवर्तन शिक्षा को वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, यद्यपि सीमित तरीके से। भारत दुनिया भर के उन कुछ देशों में से एक है जहां 1991 में एक निर्देश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा औपचारिक शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय के रूप में इसकी शुरुआत की। उच्च स्नातक छात्रों के लिए, जलवायु परिवर्तन की कुछ अवधारणाओं को उन विषयों में एकीकृत किया गया था जो पहले से ही पढ़ाए गए थे, जैसेकि विज्ञान और भूगोल।

यह रिपोर्ट उन शैक्षणिक दृष्टिकोणों का भी विश्लेषण करती है जो जलवायु परिवर्तन सीखने को बढ़ाने में अधिक प्रभावी हैं। इस तरह के शिक्षाशास्त्र शिक्षण-सीखने के अनुभव को अधिक आकर्षक बनाते हैं और स्थानीय संदर्भों में जलवायु परिवर्तन के मामलों की समझ को गहरा करते हैं, साथ ही शिक्षार्थियों की स्थानीय रूप से कार्यवाही करने और नेतृत्व करने की क्षमता को सुदृढ़ करते हैं।

दाएं: कला गतिविधियां 6 'आर' के अभ्यास के महत्व को सिखाने में मदद कर सकती हैं। द प्लैनेट डिस्कवरी सेंटर, सीईई, गुजरात।

भारत के लिए चुनौतियां

चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों, शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों और शिक्षकों के प्रयासों और गतिविधियों की आवश्यकता है ताकि कमियों को दूर किया जा सके और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

जलवायु परिवर्तन की जटिलता, भारत की शिक्षा प्रणाली के विस्तार और भारतीय शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा मुद्दों को देखते हुए, शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने का कार्य चुनौतियों के अपने सेट के साथ आता है।

यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को सार्थक ढंग से संबोधित करने वाली शिक्षा के बारे में कई चिंताओं की ओर इशारा करती है - जिनमें से पहला है जलवायु परिवर्तन शिक्षा के दायरे को पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा के साथ इसके अतिव्यापन को देखते हुए, परिभाषित करते हुए इसे पाठ्यक्रम में एकीकृत करना। इसके बाद यह पाठ्यक्रम विकासकों और पाठ्यपुस्तक लेखकों पर निर्भर हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जलवायु परिवर्तन शिक्षा और इसके स्थानीय संदर्भ के महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया जाए और उन्हें व्यवस्थित, बहुविषयक और प्रगतिशील तरीके से शामिल किया जाए।

वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों में भी खामियां हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा को प्राथमिकता दिए बिना जलवायु परिवर्तन निपटने वाली नीतियों में। यह रिपोर्ट इस संबंध में चुनौतियों के कई आयामों की पड़ताल करती है, जिसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया है - नीतियों में अंतर, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण संसाधनों से लेकर, पाठ्यक्रम में अंतर, प्रभावी शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और हरित कौशल, और वित्तपोषण और कार्यान्वयन में अंतर। इसके लिए स्कूलों, शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों और शिक्षकों के प्रयासों और कार्यवाहियों की आवश्यकता है ताकि उक्त अंतरों को पाटने और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापन और सीखने की हानि भी शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों को बढ़ाने वाली चुनौतियों में से एक है। अंत में, देश के लिए अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन शिक्षा के वित्तपोषण को एक चुनौती के रूप में पहचाना गया है।

भारत के लिए अवसर

हालांकि जलवायु परिवर्तन शिक्षा के संबंध में चुनौतियां हैं, लेकिन इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने के अवसर भी हैं। यह भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता का लाभ उठाने के साथ-साथ एक जलवायु-लचीले समाज का निर्माण करना संभव है जो जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करने और प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को अनुकूलित कर सके।

पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के पहले अवसरों में से एक स्कूल शिक्षा के लिए 2023 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आगामी कार्यान्वयन में पेश किया गया है, जो शिक्षा हितधारकों को सभी ग्रेड और विषयों में स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अद्यतन और संशोधित करने का मौका प्रदान करता है। इससे बहुविषयी दृष्टिकोण, स्थानीय संदर्भ और सिस्टम सोच को अपनाकर, विभिन्न विषयों और ग्रेडों में व्यवस्थित, प्रगतिशील और समग्र तरीके से जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं और सामग्री को एकीकृत करने की चुनौती का समाधान करने का अवसर खुल जाएगा।

एकीकरण से पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने और विकसित करने की संभावना भी बनी रहती है जो शिक्षकों और शिक्षाविशारदों को जलवायु परिवर्तन और स्थिरता जैसे समसामयिक विषयों को सीखकर निरंतर व्यावसायिक विकास प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

यह शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण-अध्ययन दृष्टिकोणों और शिक्षाशास्त्रों की ओर उन्मुख करेगा जिन्हें प्रभावी जलवायु परिवर्तन सीखने के लिए अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा प्रणाली को पूरे स्कूल की भागीदारी से काफी फायदा हो सकता है, जैसेकि बढ़ी हुई जलवायु सुरक्षा के लिए स्कूल सुविधाओं और संचालन को उन्नत करना, उनके शासन में स्थिरता पहलुओं को अपनाना, और समुदायों के साथ जुड़ना और साझेदारी बनाना। इसके परिणामस्वरूप, स्कूल प्रणालियों को अधिक लचीला, समावेशी और जलवायु-अनुकूल मूल्यों और दृष्टिकोणों के प्रति जागरूक होने और शिक्षार्थियों को जो उपदेश दिया जाता है, उसका अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल स्तर पर इन पहलों के अलावा, उच्च शिक्षा स्तर में भी जलवायु परिवर्तन शिक्षा को एकीकृत करने की अपार संभावनाएं हैं, एक उल्लेखनीय उदाहरण पूर्वस्नातक स्तर की पर्यावरण शिक्षा (यूजीसी, 2023) के लिए दिशानिर्देशों और पाठ्यक्रम रूपरेखाओं की हाल में की गई शुरूआत है।

अंतत: यह रिपोर्ट समुदायों को सशक्त बनाने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर पुनर्विचार और संरक्षण करने और जलवायु कार्यवाही के स्वामित्व को बनाए रखने और देश भर में जलवायु शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारत में सभी हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है।

7 अनुशंसाएं

अनुशंसा 1
शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता पर जोर दें

कई प्रमुख मील के पत्थर शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता की भारत की प्रारंभिक मान्यता की याद दिलाते हैं, विशेष रूप से पिछली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं (1975, 1988); पर्यावरण शिक्षा के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना (1984); और भारत में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश (1991)। इन ऐतिहासिक निर्णयों ने पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए शिक्षा की भूमिका को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी शामिल है।

आज, चूंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांत पर जोर देना और जलवायु परिवर्तन शिक्षा के पहलुओं को एकीकृत करना और भी महत्वपूर्ण है ताकि समझ बनाई जा सके और उन मूल्यों को विकसित किया जा सके जो स्थायी जीवन शैली और जलवायु पर सामूहिक कार्यवाही का नेतृत्व करते हैं। एक आदर्श परिदृश्य में, सभी व्यक्तियों को जलवायु परिवर्तन की व्यक्तिगत या स्थानीय प्रासंगिकता का एहसास होना चाहिए और आत्म-प्रेरणा की भावना से उन्हें जमीन पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। ऐसी कार्यवाही के कुछ उदाहरणों में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करना, संसाधनों का संरक्षण करना या दीर्घकालिक नीतियों की वकालत करना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, मानसिकता में बदलाव, व्यवहार में बदलाव और शैक्षणिक संस्थानों, नीति-निर्माताओं, गैर-सरकारी संगठनों, युवाओं और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। अपने अतीत से सबक लेकर और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करके, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को एक स्थायी भविष्य बनाने और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है।

अनुशंसा 2
सभी विकास नीतियों में जलवायु परिवर्तन शिक्षा घटक को शामिल करें

जलवायु परिवर्तन शिक्षा को विकास की बड़ी चुनौती के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए जो टिकाऊ और समावेशी तरीके से सभी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करे। इसके लिए प्रत्येक विकास-संबंधी नीति, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर निपटने वाली नीति में जलवायु-संबंधी मुद्दों से निपटने की रणनीतियों में से एक के रूप में शिक्षा को स्पष्ट रूप से एकीकृत करने के लिए एक समर्पित घटक की सुविधा की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की क्षमता का एहसास करने के लिए, भारत में हर विकास-संबंधी नीति में इसके एकीकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो कई कार्यक्षेत्रों और क्षेत्रों को प्रभावित करती है, और शिक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का एक आवश्यक नीतिगत तत्व है। अपनी अंतःविषय प्रकृति के साथ शिक्षा, जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों को पहचानने और समझने के लिए शिक्षार्थियों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए उन्हें ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से लैस कर सकती है। इसमें शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सटीक जलवायु जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

निर्बाध एकीकरण प्राप्त करने के लिए, नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, युवाओं, शिक्षकों और छात्रों सहित शिक्षा हितधारकों को जलवायु नीतियों के भीतर शिक्षा को प्राथमिकता देने की वकालत करनी चाहिए। ऐसा करके, भारत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित एक जानकार समाज का निर्माण कर सकता है।

अनुशंसा 3
शिक्षा के सभी चरणों में जलवायु परिवर्तन शिक्षा को समाहित करें

जलवायु परिवर्तन शिक्षा को आशा और आशावाद का एक सकारात्मक संदेश देना जरूरी है, और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटते हुए उस विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है जो सभी देशों का अधिकार और आकांक्षा है। उस सीमा तक, जलवायु परिवर्तन शिक्षा को उचित रूप से दीर्घकालिक विकास की बड़ी योजना के भीतर रखना होगा।

जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षार्थियों की समझ को अद्यतन करने और समाधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समस्या-समाधान और महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा भारतीय पाठ्यक्रम के भीतर जलवायु परिवर्तन शिक्षा के प्रभावी एकीकरण को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के मुद्दों निपटने के लिए मौजूदा शिक्षा कार्यक्रमों को विभिन्न आयु समूहों और शिक्षा के स्तरों के अनुसार पुन: उन्मुख और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, ताकि जैसे-जैसे शिक्षार्थी परिपक्व हों और उनकी समझ विकसित हो, इन अवधारणाओं को बढ़ती गहराई और जटिलता के साथ प्रस्तुत किया और सिखाया जा सके। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समग्र विकास और स्थिरता पर जोर देता है।

बुनियादी और प्रारंभिक चरण से शुरू करके, छात्रों को स्थायी आदतें विकसित करनी चाहिए और संरक्षण के मूल्यों और प्रकृति एवं संस्कृति में उनकी जड़ों के बारे में सीखना चाहिए। मध्य चरण में, छात्रों को सकारात्मक कार्यों और हरित कौशल पर जोर देते हुए अंत:विषय जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं से परिचित कराया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर, छात्र विशिष्ट जलवायु प्रभावों, कमजोरियों, न्याय और कार्यों में गहराई से उतर सकते हैं और अनुभवात्मक शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर, छात्रों को गहन जलवायु ज्ञान, शमन और अनुकूलन नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और जलवायु परिवर्तन के पर्यावरण-मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

विभिन्न विषयों और स्तरों पर जलवायु शिक्षा के साथ सीखने के परिणामों को संरेखित करने से व्यापक कवरेज भी सुनिश्चित होगी और जलवायु परिवर्तन के बारे में सीखने की अंत:विषय प्रकृति पर प्रकाश डाला जाएगा। यह समग्र, स्टेज-विशिष्ट दृष्टिकोण शिक्षार्थियों में जलवायु परिवर्तन की गहरी समझ को बढ़ावा देगा, इस वैश्विक मुद्दे के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध विकसित करेगा और जिम्मेदार जलवायु कार्यवाही और शमन के प्रति उनकी भागीदारी को प्रेरित करेगा।

नीचे: बुनियादी स्तर पर सीखना: बच्चे एक मनोरंजक गतिविधि में पेड़ की छाल का पता लगाते हैं। द प्लैनेट डिस्कवरी सेंटर, सीईई, गुजरात।

अनुशंसा 4
शैक्षणिक संस्थानों को हरित और जलवायु के लिए तैयार रहने में सहायता करें

शिक्षा की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों को जलवायु चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, शैक्षणिक संस्थानों को हरित और जलवायु-लचीले वातावरण में बदलने की आवश्यकता है। इस पहल में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा प्रणाली, जल प्रबंधन, अपशिष्ट में कमी, हरित स्थान और आपदा तैयारी सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

जलवायु-अनुकूल भवन डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और टिकाऊ जल प्रथाओं को अपनाकर, संस्थान अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। देशी पौधों के साथ हरित स्थान बनाने से न केवल जैव विविधता बढ़ती है, बल्कि छात्रों के लिए पारिस्थितिक अवधारणाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए रहने योग्य कक्षाएं भी बनती हैं।

छात्रों को जलवायु-संबंधी परियोजनाओं में शामिल करने से व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलता है और उन्हें जलवायु के प्रति जागरूक नागरिक बनने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा, इन प्रयासों में समुदायों को शामिल करने से स्थानीय समाधान और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामित्व पैदा होता है और कार्यवाही की निरंतरता को प्रोत्साहित किया जाता है।

यह अनुशंसा राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और शैक्षिक मूल्यों के अनुरूप है, प्रायोगिक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए नीति समर्थन, सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता है कि भारत में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान भविष्य में एक स्थायी और जलवायु-तैयार के रूप में योगदान दे।

अनुशंसा 5
हरित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य को शामिल करें

स्थायी रोजगार को बढ़ावा देते हुए हरित और शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की मांगों को पूरा करने के लिए, भारत की शिक्षा प्रणाली में जलवायु-परिवर्तन से संबंधित हरित कौशल को शामिल करना आवश्यक है। यह एकीकरण प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक सभी शैक्षिक स्तरों तक फैला होना चाहिए।

शिक्षा प्रणाली को हरित कौशल की बढ़ती आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और शिक्षार्थियों को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल प्रबंधन और संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, टिकाऊ वस्त्र, कृषि स्थिरता, वन और वन्यजीव प्रबंधन, हरित निर्माण, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, जलवायु

नीचे: लड़कियां किचन गार्डन गतिविधि के दौरान बीज बोना सीखती हैं, सरकारी हाई स्कूल, तमिलनाडु।

दाएं: एक शिक्षक समझाते हैं कि बिजली ऑडिट कैसे करें। रचना स्कूल, गुजरात।

डेटा विश्लेषण, पर्यावरण-पर्यटन, टिकाऊ परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इन कौशलों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-निर्माण कार्यक्रमों में समाहित किया जाना चाहिए।

हरित कौशल और शिक्षा को बढ़ावा देकर, भारत अपने कार्यबल को हरित अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय चिंताओं से निपट सकता है बल्कि उभरते हरित रोजगार बाजार के लिए तैयार कुशल उम्मीदवारों का एक समूह बनाने में भी मदद करता है, जिससे भारत के आर्थिक विकास और स्थिरता लक्ष्यों में योगदान मिलता है।

अनुशंसा 6
व्यापक जलवायु परिवर्तन शिक्षा प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ शिक्षकों को सशक्त बनाएं

जलवायु परिवर्तन के संबंध में छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को आकार देने में शिक्षक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। शिक्षा में जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, सेवा-पूर्व और सेवाकालीन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, विषयों और गतिविधियों में जलवायु परिवर्तन शिक्षा को समाहित करने से विषयों और शिक्षण के बीच संबंध बनेंगे और शिक्षक जलवायु परिवर्तन को पढ़ाने के बारे में अधिक आश्वस्त होंगे।

पूर्व-सेवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भीतर समर्पित जलवायु परिवर्तन शिक्षा मॉड्यूल को शामिल करने से भविष्य के शिक्षकों को किसी अन्य स्वचलित और जटिल विषय क्षेत्र में महारत हासिल करने के बोझ को बढ़ाए बिना अपने शिक्षण में जलवायु परिवर्तन विषयों को प्रभावी ढंग से समाहित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान से लैस किया जाएगा। इन मॉड्यूल्स में प्रासंगिक शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहिए और नवीन तरीकों से शिक्षण को सक्षम बनाना चाहिए।

इन कार्यक्रमों में आयु-उपयुक्त शिक्षण विधियों को नियोजित करने, छात्रों को व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न करने, कक्षा में चर्चा की सुविधा प्रदान करने और स्थायी व्यवहार को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसे नियमित और समर्पित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास से यह सुनिश्चित होगा कि मौजूदा शिक्षकों को जलवायु परिवर्तन के बारे में सटीक और अद्यतन ज्ञान प्राप्त हो।

ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को इस तरह से निर्देश और समर्थन प्राप्त हो जिससे वे जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में समझने के बजाय अपने दैनिक शिक्षण में सहजता से समाहित कर सकें। इस दिशा में, शिक्षकों को ज्ञान, प्रभावी शिक्षाशास्त्र और उपकरणों से लैस होना चाहिए जो पर्यावरण और जलवायु को सीखने और कार्यवाही के लिए समग्र, संपूर्ण-स्कूली दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

ऊपर: सामूहिक कार्यवाही: पौधों की सिंचाई के लिए एक टीम के रूप में काम करना। संजीवनी औषधीय उद्यान, गुजरात।

अनुशंसा 7
हरित भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं के साथ जुड़ें

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विविध चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को शामिल करना अतिआवश्यक है। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन पर निर्णयों में युवाओं को शामिल करना उन लोगों को उन कार्यों में शामिल करना जिनका भविष्य प्रभावित होगा जिनका उद्देश्य उनके भविष्य को सुरक्षित करना है, एक जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यापक नीति की आवश्यकता है जो युवाओं को जलवायु कार्यवाही में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाए। इसमें युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करना शामिल है जो विशिष्ट जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हैं, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए जलवायु शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, और जलवायु नीतियों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा, युवाओं को मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए जो प्रभावी जलवायु कार्यवाही के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और कौशल प्रदान करते हैं, उन्हें हरित रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक योग्यताओं से लैस करते हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने से स्थानीय और वैश्विक संदर्भों के अनुरूप नए समाधान प्राप्त हो सकते हैं। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और विविधता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों के युवाओं को उनके जुनून, रचनात्मकता और नए दृष्टिकोण के साथ जोड़कर, ऐसे समाधान निकाले जा सकते हैं जो एक बड़े देश की विभिन्न भौगोलिक और प्रासंगिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होता है बल्कि युवाओं को अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का अधिकार भी मिलता है।

अनुशंसा 8
जलवायु परिवर्तन शिक्षा में कम-कार्बन जीवन शैली का समर्थन करने वाले स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करें

भारत के मिशन LiFE पहल के अनुरूप और जलवायु परिवर्तन शिक्षा को बढ़ाने के लिए, इस देश को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों के बीच बंधन को मजबूत करे। इस दृष्टिकोण में स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ फिर से जुड़ना शामिल है जो स्थिरता और कम कार्बन वाले जीवन की वकालत करते हैं। भारत ऐसे ज्ञान का खजाना होने का दावा करता है, जो टिकाऊ संसाधन प्रबंधन, अपशिष्ट कटौती और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सहित सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परंपराओं में निहित है। यदि उचित रूप से उपयोग किया जाए, तो ऐसा पारंपरिक ज्ञान आधुनिक, वैज्ञानिक प्रथाओं और समझ में नए दृष्टिकोण ला सकता है और जीवन के भविष्य के तरीकों को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है।

छात्रों को किसानों, कारीगरों और आदिवासी बुजुर्गों सहित समुदाय के सदस्यों के साथ उनकी विशेषज्ञता और उनके पिछले अनुभवों से सीखने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि-पारिस्थितिकी ज्ञान, योग और जल संरक्षण तकनीक जैसी पारंपरिक प्रथाएं दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन स्थानीय परंपराओं को जलवायु परिवर्तन शिक्षा में समाहित करने से भविष्य के नेताओं का पोषण किया जा सकता है जो देश की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित करते हुए और उनका उत्सव मनाते हुए जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे।

अनुशंसा 9
जलवायु परिवर्तन शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करें

भारत में सभी शैक्षिक चरणों में समग्र जलवायु परिवर्तन शिक्षा प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रचनात्मक नवाचारों को बढ़ावा देने वाले शिक्षा हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना अनिवार्य है। इस सहयोगात्मक प्रयास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र (विभिन्न शिक्षा बोर्डों, संबद्ध संस्थानों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंधनों सहित), उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विचार मंचों, युवाओं, बहुपक्षीय धनप्रदाताओं, सेक्टर विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के शामिल किया जाना चाहिए।

ये साझेदारियां संसाधनों, निधियों, विशेषज्ञता और ज्ञान के समन्वय तथा साझाकरण की सुविधा प्रदान करेंगी, जिससे जलवायु परिवर्तन शिक्षा के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। यह सहयोग मानकीकृत पाठ्यक्रम, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों और शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास तथा आयु-उपयुक्त जलवायु जानकारी के विस्तार को सक्षम बनाएगा।

अनुशंसा 10
जलवायु परिवर्तन पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा-केंद्रित पोर्टलों को मजबूत और सृजित करें

जलवायु परिवर्तन एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र है, जिसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अनुसंधान, पहल, रणनीतियों, नीतियों और समाधानों के अद्यतन ज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान और विश्वसनीय जलवायु परिवर्तन की जानकारी तक व्यापक और अच्छी तरह से समन्वित पहुंच और प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, भारत नए ऑनलाइन प्लेटफार्म सृजित करने पर विचार कर सकता है, इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों को भी बढ़ावा दे सकता है।

इन प्लेटफार्मों को, एक व्यापक नीति रणनीति के हिस्से के रूप में, छात्रों, शिक्षाविशारदों, शोधकर्ताओं और व्यापक समुदाय सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन शिक्षा हेतु मूल्यवान संसाधनों के रूप में सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। इन ऑनलाइन प्लेटफार्मों को अद्यतन सामग्री बनाए रखनी चाहिए जो शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, और ये ग्रेड-विशिष्ट और मूल विषय-विशिष्ट जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करें। उन्हें ऐसे केंद्रों के रूप में काम करना चाहिए जिनमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित नवीन शैक्षणिक तरीकों को संकलित किया जा सके, जिससे समाज के भीतर एक गतिशील और आकर्षक सीखने के माहौल को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, जानकारी को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मौजूदा संसाधनों की प्रभावशीलता को मजबूत करने से धीमी गति से अद्यतन होने वाली पाठ्यपुस्तकों और जलवायु परिवर्तन की गतिशील प्रकृति के बीच अंतर को पाटने का एक संभावित तरीका बनता है।

दाएं: छात्र कार्टूनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के बारे में सीख रहे हैं। रचना स्कूल, गुजरात।

जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर यूनिसेफ इंडिया की पहल

unicef
for every child

भारत में जलवायु परिवर्तन को उत्तरोत्तर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना जा रहा है। विशेषकर बच्चों में जलवायु परिवर्तन को लेकर स्वीकार्यता बढ़ रही है क्योंकि इससे उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को जलवायु संकट के प्रभावों को समझने और संबोधित करने में मदद करती है, उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों के साथ सशक्त बनाती है। हाल के दिनों में, यूनिसेफ ने नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा(एनसीएफ) में जलवायु परिवर्तन तत्वों को समाहित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए पर्यावरण शिक्षा पर राष्ट्रीय फोकस समूह के सदस्यों के साथ काम किया है। राज्य, एनसीएफ को अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करेंगे और स्कूलों में उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के अपने संस्करण तैयार करेंगे। यूनिसेफ राज्य सरकारों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख तत्वों को एकीकृत करने के लिए चल रहे मौजूदा कार्यक्रमों का भी उपयोग कर रहा है। इनमें स्कूल स्तर पर स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, बाल कैबिनेट, किशोर और युवा मंच शामिल हैं। ये सभी मौजूदा हस्तक्षेप संबंधित राज्य सरकारों और भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित यूनिसेफ इंडिया के प्रमुख हस्तक्षेपों की रूपरेखा नीचे रेखांकित की गई है:

1 स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन का समाकलन

- बिहार में, यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) ने 70,000 स्कूलों के 8.4 मिलियन बच्चों तक पहुंचने वाले, चल रहे व्यापक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के तत्वों को एकीकृत किया है।
- छत्तीसगढ़ में, यूनिसेफ ने 45000 स्कूलों में 37,000 शिक्षकों के सहयोग से 5 मिलियन बच्चों तक पहुंचने वाले स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को शुरू करने में समग्र शिक्षा का समर्थन किया है।
- जम्मू और कश्मीर में, लगभग 1000 स्कूलों में 30,000 बच्चों और 5000 शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के साथ एक व्यापक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
- गुजरात में, यूनिसेफ ने 33000 से अधिक स्कूलों तक पहुंचने वाले स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर स्व-चालित पाठ्यक्रम के विकास में समग्र शिक्षा और जीआईडीएम का समर्थन किया है।

2 किशोर प्लेटफॉर्म

- उत्तर प्रदेश में, जलवायु परिवर्तन पर बाल सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 240 उच्च प्राथमिक और समग्र विद्यालयों के 6,000 बच्चों की भागीदारी के साथ किया गया था। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर एक सप्ताह तक चले अभियान का समापन था
- यूनिसेफ ने राज्य के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 45,000 किशोर मीना मंच प्लेटफार्मों द्वारा जलवायु परिवर्तन अभियान को राज्यव्यापी स्तर पर बढ़ाने की सफलतापूर्वक वकालत की।

3 पाठ्यक्रम

- केरल में, पाठ्यक्रम समीक्षा के कारण यूनिसेफ के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन उपायों को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया।
- महाराष्ट्र में, राज्य सरकार द्वारा 65000 प्राथमिक विद्यालयों और 10000 शिक्षकों को कवर करने के लिए प्रारंभिक ग्रेड के लिए यूनिसेफ के समर्थन से जलवायु और पर्यावरण एकीकरण पाठ योजनाएं विकसित की गईं

आगे की दिशा

- राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन की पहल और हस्तक्षेप को बढ़ाना
- क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों और छात्रों के लिए जलवायु कार्यवाही (डिजिटल, गैर-डिजिटल) पर शिक्षण संसाधनों/सामग्री का विकास करना
- ऑनलाइन सहित जलवायु परिवर्तन पर व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना
- नई पाठ्यक्रम रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन का एकीकरण और उसका कार्यान्वयन करना
- स्कूलों की हरियाली के लिए रूपरेखा और संकेतक विकसित करना और मानकों के विकास में सहायता करना
- जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुसंधान अध्ययन संचालित करना और साक्ष्य तैयार करना

सी ई ई

पर्यावरण शिक्षा केंद्र

पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण शिक्षा (ईई) और दीर्घकालिक विकास शिक्षा (ईएसडी) के क्षेत्र में काम कर रहा है। सीईई को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या GUJ/1043/अहमदाबाद के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका पंजीकृत कार्यालय थलतेज टेकरा, अहमदाबाद में है। एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, सीईई का कार्य देशभर में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। सीईई नवीन कार्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री को विकसित करता है और ईएसडी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यावरण शिक्षा दीर्घकालिक विकास के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। यह क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है जो दीर्घकालिक विकास में शिक्षा की भूमिका को प्रदर्शित और मान्यता प्रदान करती हैं। 200,000 से अधिक स्कूलों के व्यापक नेटवर्क के साथ, यह विभिन्न एजेंसियों के साथ साझेदारी में कई स्कूली कार्यक्रम चलाता है। सीईई भारत में शिक्षा प्रणाली में जलवायु परिवर्तन शिक्षा को मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पिछले 39+ वर्षों के दौरान, सीईई ने एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करने के लिए भारत और विभिन्न अन्य देशों में विभिन्न स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, संगठनों और सरकारों के साथ काम किया है। सीईई व्याख्या कार्यक्रम और सुविधाएं सृजित करने में वन विभागों और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करता है। सीईई सीएसआर फंडिंग के माध्यम से कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, फाउंडेशनों और कॉरपोरेट्स सहित बहुपक्षीय संगठनों के साथ साझेदारी करता है, और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा परिपत्र अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में काम करता है।

यूनेस्को नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय इस रिपोर्ट के विकास के लिए यूनिसेफ भारत, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया और मोबियस फाउंडेशन के समर्थन को स्वीकार करना चाहेगा।

पिछले कवर का चित्र
हमारे ग्रह के संरक्षण के लिए समर्पित छात्र।
श्रीमती एम. ए. जानी जीवन शाला, गुजरात।

1 सैन मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली 110 021, भारत
फोन: +91-11-2611 1873/5 एवं 2611 1867/9
ईमेल: newdelhi@unesco.org
वेबसाइट: https://www.unesco.org/en/fieldoffice/newdelhi